ARBiT

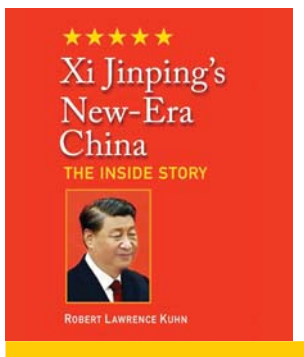
जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot



Understanding Xi Jingping's...

Understanding China's political system requires understanding how the Party implements its leadership through its hierarchical system

From Purple Carrots To Seedless Bananas

Why Water Is the Number One Enemy of Dhakai Jamdani

संसद का विशेष सत्र, मानसून सत्र जारी रखते हुए 30 नवंबर को आहूत

सरकार ने अंततोगत्वा, ''डीलिमिटेशन विधेयक'' पारित कराने का रिस्क उठाने का निर्णय लिया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। सरकार ने आखिरकार एक बड़ा और मुश्किल कदम उठाने का फैसला कर लिया है।

संसद के मानसून सत्र को आगे बढ़ाते हुए सोमवार, 30 नवंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है।

इसका एजेंडा जाहिर तौर पर परिसीमन विधेयक है।

चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए सरकार को इसे पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है, जो पिछली बार संख्या बल के हिसाब से उसके पास नहीं था।

इस पूरी कवायद के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह पिछले कुछ महीनों से विशेष सत्र बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हार के डर और पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण यह मामला टलता रहा।

- यह संविधान संशोधन विधेयक है, इसे पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए और भाजपा के रणनीति विशेषज्ञ, अमित शाह पिछले कई महीनों से यह दो-तिहाई का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे।
- भाजपा के लिए, ''डीलिमिटेशन विधेयक'' अभी ही पास करना जरूरी था अन्यथा भाजपा 2029 का आम चुनाव नई डीलिमिटेशन के अनुसार परिवर्तित सीटों पर नहीं करा पाती।
- कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संसद में अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई है।

सरकार, ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके तृणमूल सांसदों, एनसीपी और अन्य दलों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका डीएमके की है, जिसकी सरकार को सख्त जरुरत है।

सरकार के पास अब समय कम होता जा रहा है। यदि वह परिसीमन विधेयक अभी पारित नहीं करा पाती है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव नए परिसीमन के आधार पर कराना मुश्किल हो सकता है।

इसके साथ ही, सरकार 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने जा रही है।

यह एक पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि इससे उसे राजनीतिक फायदा मिलेगा, क्योंकि वह अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करना चाहती है।

कांग्रेस कल अपने संसदीय रणनीति समूह की बैठक करेगी, जिसमें विशेष सत्र और सरकार की संभावित रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

और संसद के शीतकालीन सत्र का क्या होगा? यह सवाल अभी अनिश्चित बना हुआ है।

इसके बाद बजट सत्र का क्या होगा?

सरकार का पूरा ध्यान परिसीमन पर इतना ज्यादा केन्द्रित है कि उसने बाकी सभी मुद्दों और सवालों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है।

शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, जबकि विशेष सत्र एक सप्ताह से भी कम समय के नोटिस पर बुलाया जा सकता है।

भू-रूपांतरण के बदले रिश्वत लेने वाले को 3 साल की सजा

जयपुर, 26 नवंबर। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने कृषि भूमि का भू-रूपांतरण कर उसे आवासीय में बदलने के बदले रिश्वत लेने वाले शाहपुरा तहसील के तत्कालीन कनिष्ठ सहायक जितेन्द्र कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

- शाहपुरा तहसील के कनिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा था।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने अदालत को बताया कि परिवादी अरविंद यादव ने 4 जनवरी, 2022 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उसकी शाहपुरा तहसील के बिलान्दरपुर में बीस एकड़ भूमि है, जिसे आवासीय में परिवर्तन कराने के लिए वह कनिष्ठ सहायक जितेन्द्र कुमार से मिला था। इस दौरान जितेन्द्र कुमार ने उसके भतीजे से भू-रूपांतरण कराने के बदले 65 हजार रुपए मांगे। इस दौरान अभियुक्त जितेन्द्र कुमार ने काम नहीं होने का भय दिखाकर उससे 45 हजार रुपए भी ले लिए। इस राशि में से 25620 रुपए की रसीद अभियुक्त ने दे दी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त बीस हजार रुपए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूपी में रोचक ''पोस्टर युद्ध'' शुरु, चुनाव की तैयारी में

भाजपा के पोस्टर, सपा क शासन के ''गुंडाराज'' का स्मरण करा रहे हैं तथा योगी आदित्यनाथ की सरकार, कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा कर रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के बीच पोस्टरों की एक रंगीन जंग छिड़ गई है। राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी बात और अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

भाजपा के पोस्टरों में एक तरफ समाजवादी पार्टी के शासनकाल के पुराने दौर की तस्वीरें हैं, जिनमें गुंडाराज, नकदी और बाहुबल को दिखाया गया है। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में बेहतर कानून-व्यवस्था और विकास के दावे किए जा रहे हैं।

भाजपा के हाल के कुछ पोस्टरों में सपा-कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत का मजाक उड़ाया गया है। इनमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच कार्टून के जरिए मुक्केबाजी दिखाई गई है। वहीं, कुछ अन्य पोस्टरों में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए, नेताओं को देवी-देवताओं के रूप में दिखाया गया है या ''राधे-राधे, कमल खिला दे'' जैसे नारे लिखे गए हैं। भाजपा कार्यालयों के पास लगे कुछ पोस्टरों में सपा शासनकाल के दौरान 1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का भी जिक्र किया

- भाजपा के पोस्टरों में 1990 में कार-सेवकों पर सपा द्वारा कराई गई फायरिंग का चित्रण है।
- सपा के पोस्टर में यह कटाक्षपूर्ण मैसेज प्रदर्शित है, ''जो बुलडोज़र के साथ आए हैं, वे साईकिलों पर रवाना होंगे।''
- कांग्रेस के पोस्टरों का मैसेज है, ''दो सौ सीट पाने का हमारा जायज़ अधिकार है।''
- रायबरेली में लगे पोस्टरों में ओवैसी व चंद्रशेखर के नवगठित सामाजिक परिवर्तन मंच को भाजपा की ''बी-टीम'' के रूप में दर्शाया गया है।
- बसपा के पोस्टर ने जनता को संदिग्ध दलालों से सावधान रहने की बात दर्शित की है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आप से भाजपा में आए सांसदों का पूर्ण उपयोग कर रही है, पार्टी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। पंजाब भाजपा, जिसने अन्य दलों के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इन नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया है। पार्टी न केवल आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए कुछ राज्यसभा सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, बल्कि उन्हें चुनाव से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां भी दे रही है।

इन सात सांसदों में से कुछ को राज्य की 13 लोकसभा सीटों में से खास सीटें चुनने को कहा गया है। इन सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी।

इस साल अप्रैल में आप के 10 राज्यसभा सांसदों में से सात भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, अशोक कुमार मित्तल, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं।

- इन सांसदों को इस बात से भी आगाह किया गया है कि उनका भाजपा में भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उनको जिन सीटों की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उन सीटों पर विधानसभा चुनाव में क्या नतीज़ा रहा।

स्वाति मालीवाल दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि बाकी छह सांसद आप के टिकट पर पंजाब से राज्यसभा के लिए चुने गए थे।

इनमें से संदीप पाठक को भाजपा ने राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान, पाठक ने आप के राष्ट्रीय संगठन सचिव के रूप में उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों के अनुसार, आज भी आप के मौजूदा विधायकों के साथ उनके करीबी संबंध हैं और वे उनमें से कई को भाजपा में शामिल कराने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

भाजपा हरभजन सिंह और राघव चड्ढा जैसे सांसदों को चुनाव प्रचार में उतारने की भी योजना बना रही है। वहीं अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रमजीत साहनी को चुनाव प्रबंधन की अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

भाजपा ने आगामी चुनावों के लिए बनाई गई विभिन्न समितियों में भी इन सांसदों को शामिल किया है। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और राजिंदर गुप्ता को घोषणापत्र समिति का सदस्य बनाया गया है।

पंजाब भाजपा ने दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए एक जॉइनिंग कमेटी भी बनाई है। आप के नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखने वाले संदीप पाठक को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। पाठक को संभावित उम्मीदवारों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए वे फिलहाल सर्वे करा रहे हैं।

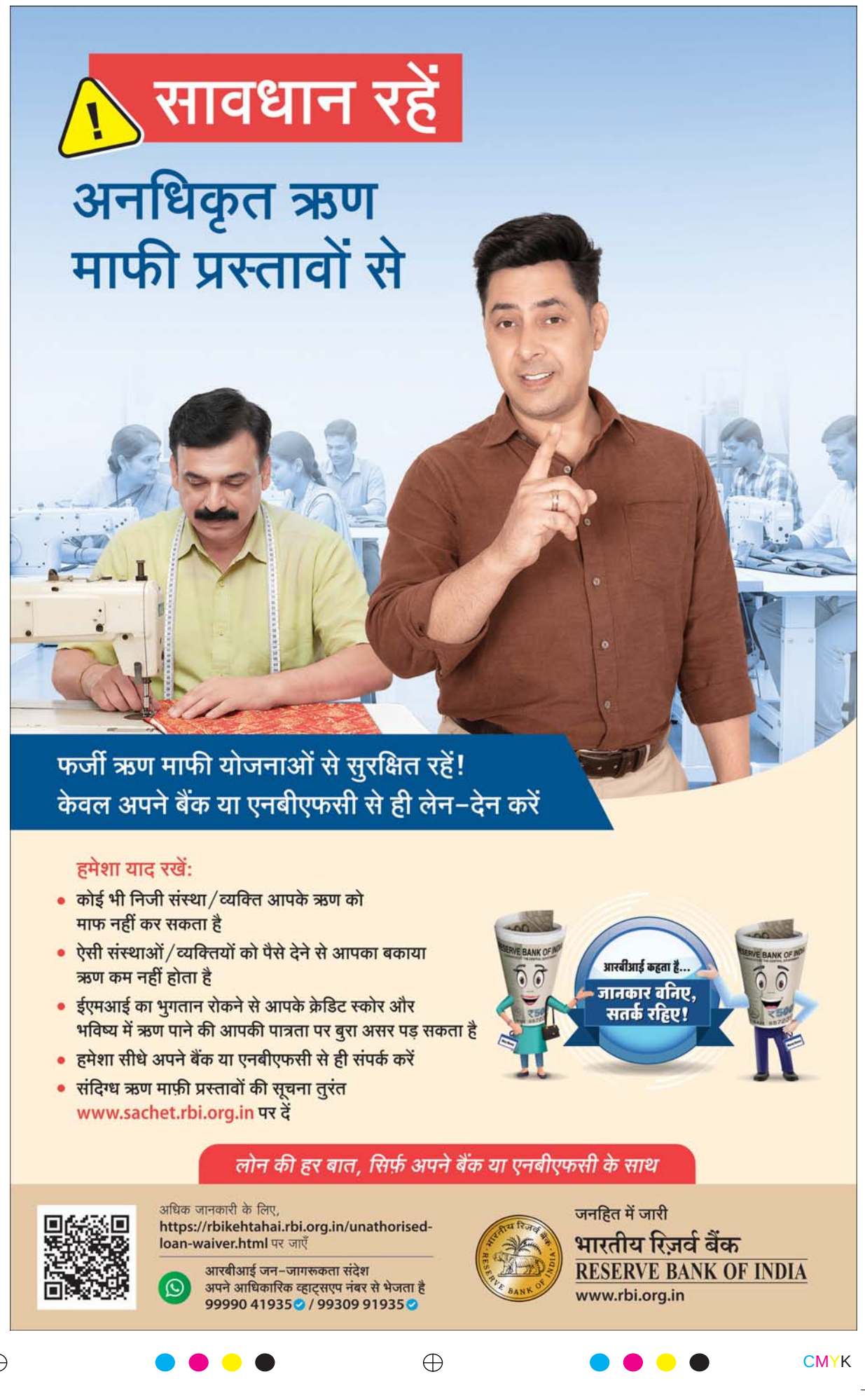
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असि. प्रोफेसर कॉलेज भर्ती परिणाम जारी करने से रोक हटी

जयपुर, 26 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज शिक्षा के लिए तीस विषयों के लिए निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती- 2025 का अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी अपनी रोक को हटा लिया है। इसके साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश देते हुए जारी होने वाले परिणाम को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश संजय व अन्य की ओर से

- आरपीएससी ने हाई कोर्ट में परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)



क्या जेनसेन हुआंग की वापसी एआई पर पूर्ण भरोसा न होने का प्रमाण है?

यह इस बात का भी सबूत है कि कॉर्पोरेट जगत में अभी भी व्यक्तिगत संबंध सबसे ज्यादा मायने रखते हैं

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। एनवीडिया के सीईओ के रूप में जेन्सेन हुआंग की वापसी, आर्टिफिशल इंटेलिजैंस में भरोसे की कमी को साफ तौर पर दर्शाती है। चार ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी में हुआंग को फिर से सीईओ बनाया गया है।

एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग को एक चीनी महिला के साथ अफेयर चलाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। वह महिला सिंगापुर की एक टैक्नॉलजी कंपनी की प्रमुख होने का दावा कर रही थी। यह चीनी जासूस, एलिस हुआंग सिंगापुर में मेगास्पीड नाम से एक टैक्नॉलजी कंपनी चला रही थी।

चीनी जासूस के साथ अपने संबंधों का खुलासा होने के बाद, जेन्सेन हुआंग ने अपने कार्यकारी पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन डॉनल्ड ट्रंप ने दखल देकर जेन्सेन हुआंग की दोबारा नियुक्ति करवाई। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स ने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी वापसी नहीं होगी, लेकिन बाद में बोर्ड को अपना फैसला बदलना पड़ा।

राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आकर बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स ने खुद ही हुआंग की सीईओ के रूप में वापसी की घोषणा की। माना जा रहा था कि यदि हुआंग वापस नहीं आते, तो एनवीडिया के बाजार मूल्य पर असर पड़ता और इसके साथ ही पूरा अमेरिकी पूंजी बाजार नीचे आ जाता।

- शर्म आती है सुनकर, कि ट्रंप को भी व्यक्तिगत रूप से हुआंग की वापसी से 15 मिलियन डॉलर का लाभ हुआ।

लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, यानी एआई के उत्पाद इतने शक्तिशाली और प्रभावी हैं, तो फिर हुआंग जैसे सीईओ की इतनी जरूरत क्यों थी? एनवीडिया के इस दिग्गज सी.ई.ओ. ने जो नतीजे दिए, क्या वे ए.आई. मॉडल और टूल के जरिए हासिल नहीं किए जा सकते थे? आखिर जेन्सेन हुआंग की इतनी ज़रुरत क्यों थी?

असल में राजनीतिक आकाओं के निजी हित सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)